दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 24 जुलाई 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 297

रक्षा क्षेत्र में और मजबूत होगा देश

सरकार ने रक्षा मंत्रालय के लिए किया 6,21,940 करोड़ रूपए का आवंटन

नई दिल्ली । आरएनएस

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया। इस आम बजट में कई बड़े ऐलान के साथ तमाम मंत्रालयों के लिए धन का आवंटन किया गया है।

इसी कड़ी में राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय को आवंटित बजट के लिए मोदी सरकार का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जहां तक रक्षा मंत्रालय के आवंटन का सवाल है, मैं 6,21,940.85 करोड़ रुपये का उच्चतम आवंटन देने के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के कुल बजट का 12.9 प्रतिशत है। 1,72,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा। घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 1,05,518.43 करोड़ रुपये निर्धारित करने से आत्मनिर्भरता को और गति मिलेगी।

उन्होंने आगे लिखा, मुझे खुशी है कि सीमा सडक़ों को पूंजीगत मद के तहत पिछले बजट की तुलना में आवंटन में 30 प्रतिशत की वृद्धि दी गई है। बीआरओ को 6,500 करोड़ रुपये का यह आवंटन हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और गति देगा। रक्षा उद्योगों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और इनोवेटर्स द्वारा दिए गए तकनीकी समाधानों को वित्तपोषित करने के लिए आईडीईएक्स योजना के लिए 518 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उन्होंने आगे लिखा, वित्त वर्ष 2024-25 बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई। यह बजट एक समृद्ध और आत्मनिर्भर 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। समावेशी और तेज गति वाले विकास की दृष्टि से यह बजट भारत के आर्थिक परिवर्तन को गति देगा। यह बजट कई मायनों में अद्वितीय है और सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए एनडीए सरकार की 9 प्रमुख प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। उन्होंने आगे लिखा, यह बजट 2027 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। भारत के किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के समर्थन के लिए कई नीतियों और कार्यक्रमों की भी घोषणा की गई है। बुनियादी ढांचे, कृषि, बैंकिंग, ऊर्जा, उद्योग, अनुसंधान एवं विकास, एमएसएमई और रक्षा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

अब हर महीने 300 यूनिट बिजली मिलेगी फ्री, बजट में सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

नई दिल्ली । आरएनएस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। बजट में पीएम सूर्योदय योजना के तहत एक करोड़ से अधिक घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री देने का ऐलान किया गया है। दरअसल, पैदा होने वाली सोलर एनर्जी सीधे उस घर को मिलने के बजाय पहले सप्लाई ग्रिड में जाएगी। ऐसे हर एक घर को प्रति महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी।

निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए और 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए। विद्युत भंडारण और समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीनकरणीय ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए पम्पड स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति लाई जाएगी। परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों और स्माल और माड्यूलर परमाणु रिएक्टर का अनुसंधान और विकास उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर (एयूएससी) प्रौद्योगिकी के प्रयोग से एनटीपीसी और बीएचईएल का एक संयुक्त उद्यम परिपूर्ण 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

हार्ड टू एबेट उद्योगों के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। जिससे इन उद्योगो को वर्तमान परफार्म, एचीव एंड ट्रेड पद्धति से इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त बनाया जाएगा। 60 क्लस्टरों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा से स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली भंडारण और समग्र ऊर्जा मिश्रण में सुचारु एकीकरण के लिए पंप स्टोरेज नीति लाई जाएगी।

1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका, महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़

नई दिल्ली (आरएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा, 'सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।' सीतारमण ने कहा, 'महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।

छात्रों के लिए बड़ा ऐलान, सरकार देगी 10 लाख रुपए तक का कर्ज

नई दिल्ली (आरएनएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने 'भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है। मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। निर्मला सीतारमण का लगातार 7वां बजट है। उन्होंने कहा, 'सरकार का फोकस गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा 'हमने पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया। इससे 80 करोड़ से अधिक गरीबों को लाभ हो रहा। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम की 5 योजनाओं के पैकेज की घोषणा। इससे 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा।

रोजगार और स्किल पर 2 लाख करोड़ खर्च करेगी सरकार, ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन पर इंसेंटिव भी मिलेगा

नई दिल्ली । आरएनएस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार 7वां बजट है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। भारत में महंगाई दर लगातार कम हो रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा, ये बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस है। वित्त मंत्री ने रोजगार पर भी बड़ा ऐलान किया है।

वित्त मंत्री ने रोजगार पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने पर हैं। बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान पर जोर है। सरकार सबका साथ, सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार बजट में युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।

रोजगार के 2 लाख करोड़ खर्च करने के अलावा सरकार ने कहा कि रोजगार देने वाले को सरकारी मदद मिलेगी। 10 लाख युवाओं को श्वक्कस्नह से फायदा हुआ है। ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन पर इंसेंटिव मिलने का भी ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बार सरकार का फोकस रोजगार पैदा करने पर है और इसके लिए 5 स्कीम लेकर आई जाएंगी। रोजगार के मौकों के लिए 5 स्कीम का ऐलान किया गया है और रोजगार के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि 20 लाख युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव देगी और रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव की 3 स्कीम लाई जाएंगी। क्करू योजना के तहत 3 चरणों में इंसेंटिव दी जाएगी, इंडस्ट्री के साथ मिलकर वर्किंग हॉस्टल बनाएंगे।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की होगी शुरुआत, बाढ़ के लिए 11,500 करोड़ के पैकेज की घोषणा

नई दिल्ली । आरएनएस

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण को शुरू करने की घोषणा की गई। साथ ही बजट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर तरह के मौसमों के अनुकूल सडक़ें उपलब्ध कराई जाएंगी।

वित्त मंत्री ने कहा, बिहार में आए दिन बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। केंद्र सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। असम में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा, बाढ़ से प्रभावित हिमाचल प्रदेश को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए सहायता मिलेगी। साथ ही उत्तराखंड में भूस्खलन और बादल फटने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है। मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है।

इस बजट में वित्त मंत्री ने पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है, जिसके जरिए पूर्वी भारत को चमकाने की सरकार की योजना है। केंद्र ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे पूर्व के राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की। इसके तहत मानव संसाधन विकास, बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जाएगा। बिहार से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही थी। लेकिन इसके बदले सरकार ने बिहार को कई सौगात दी है। निर्मला सीतारमण ने बिहार को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने को लेकर कहा, बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास का समर्थन करेंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। हम पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा सडक़ संपर्क परियोजनाओं के विकास का भी समर्थन करेंगे और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा।

एमएसएमई सेक्टर में मिलेगा 100 करोड़ तक का लोन, पीएम मुद्रा लोन योजना की राशि भी हुई दोगुनी

नई दिल्ली । आरएनएस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट भाषण में एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा करते हुआ कहा कि इस सेक्टर में अब 100 करोड़ रुपये तक लोन दिए जा सकेंगे। सरकार की तरफ से एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना में छोटे कारोबारियों के लिए नई क्रेडिट स्कीम का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सिडबी इस साल 24 नए ब्रांच खोल सकेगा।

एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहे इसके लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए पीपीपी मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है। पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत अब 20 लाख तक के लोन दिए जाएंगे। पहले इसके तहत 10 लाख तक के लोन देने का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। बता दें कि सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार के साथ जोडऩे के लिए इस योजना को लागू किया था। इस योजना के तहत पहले युवाओं को नए रोजगार के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाता था। वहीं इस बात वित्त मंत्री ने लोन की सीमा को बढ़ाकर अब 20 लाख तक कर दिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातवीं बार सदन में आम बजट पेश कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। इस केंद्रीय बजट में निर्मला सीतारमण ने 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रूपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3त्न की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

इसके साथ ही देश के युवाओं के लिए इस बजट में वित्त मंत्री ने जो ऐलान किया है उसके अनुसार रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इसमें 500 टॉप कंपनियों में पांच करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान भी है।

इसके साथ ही पहली जॉब ज्वाइन करने वाले युवाओं के लिए 15 हजार की तीन किश्त सीधे ईपीएफओ अकाउंट में दिया जाएगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि पहली नौकरी वालों के लिए एक लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।

उत्तर पूर्व में 100 से अधिक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शाखाएं स्थापित करने की घोषणा

नई दिल्ली । आरएनएस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में अपना सातवां बजट पेश करते हुए घोषणा की कि उत्तर पूर्व में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के पूर्वोत्तर के विकास के दृष्टिकोण को यह कदम दर्शाता है।

आईपीपीबी देश के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों को विभिन्न उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने में सबसे आगे है। यह डोर स्टेप बैंकिंग (डीएसबी) सेवाओं के साथ ग्राहकों को घर पर बैंकिंग सुविधाओं का अवसर भी देता है। इंडिया पोस्ट के व्यापक नेटवर्क के कारण, लाखों ग्राहकों को सहायक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 1.36 लाख से अधिक डाकघर देश के सबसे दूरदराज के इलाकों तक बैंकिंग को सुलभ बना रहा है।

इस साल की शुरुआत में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसके आठ करोड़ ग्राहक अब इसकी वित्तीय सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।

डाक विभाग के तहत स्थापित आईपीपीबी की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है। इसे 1 सितंबर, 2018 को लॉन्च किया गया था। स्थापना के बाद से, आईपीपीबी देश के हर कोने में सुलभ और किफायती बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए समर्पित रहा है।

नीट यूजी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली । आरएनएस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट-यूजी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि परीक्षा रद्द करने की मांग सही नहीं है। इसका मतलब है कि नीट-यूजी परीक्षा दोबारा नहीं होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे ये साबित हो कि पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है।

बता दें कि कई छात्र नीट-यूजी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे थे। उन लोगों ने इसमें कई अनियमितताओं का आरोप लगाया था। यहां तक कि पेपर लीक का भी आरोप लगा। बताया गया कि इसमें कई खामियां हैं। नीट-यूजी परीक्षा 571 शहरों के 4750 केंद्रों के अलावा 14 विदेशी शहरों में भी आयोजित की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रीनीट यानी दोबारा परीक्षा नहीं होगी, इसमें काफी ज्यादा खर्च आएगा। एडवोकेट श्रुति चौधरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी की दलीलें सुनी, सीबीआई की जांच रिपोर्ट देखी, और फिर फैसला किया कि रिकॉर्ड पर इतना सबूत ही नहीं है दोबारा परीक्षा का आदेश पारित किया जाय। जो चीटिंग हुई थी वो पटना और हजारीबाग के अलावा कहीं नहीं हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने कम सबूत के आधार पर अगर दोबारा परीक्षा होगी तो 23 लाख उम्मीदवारों के लिए सुविधाजनक नहीं होगा। कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) से भौतिकी के एक विवादास्पद प्रश्न के संबंध में आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञ पैनल द्वारा दी गई राय के मद्देनजर अंकों को नए सिरे से मिलान करने को कहा, जिसमें कहा गया कि दो विकल्पों को एक प्रश्न का सही उत्तर नहीं माना जा सकता।

बजट 2024 में कृषि पर विशेष फोकस, हुए बड़े ऐलान

नई दिल्ली । आरएनएस

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किया। बजट पेश होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह आम बजट अमृत काल के लिहाज से अहम होगा। यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2024 तक विकसित भारत की आधारशिला रखने में अहम भूमिका निभाएगा।

बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसानों पर विशेष फोकस किया है। वित्त मंत्री ने देश के 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही झींगा, मछली, ब्रूडस्टॉक के लिए केंद्रीयकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध करने का भी ऐलान किया है। वहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने की घोषणा की।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में नौ प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। इसमें खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार सहित अन्य कारकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है।

वित्त मंत्री ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, जो चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर है। गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।'

उन्होंने कहा कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपए का बजट है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे दो लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पांच योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।